(c) Approximately 1543-cases in major units of BHEL.

(d) Since employment on compassionate grounds is need-based, it is difficult to fix a time frame for disposing of all such requests.

एच.एम.टी. कारखाना , अजमेर का कार्यकरण

3559. **श्री ओंकार सिंह लखावतः क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) देश में हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी) के कितने कारखाने हैं और उनका राज्य वार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या अजमेर स्थित एच एम. टी . कारखाने ने गत तीन वर्षों में उत्पादन लक्ष्य हासिल किए हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या अजमेर स्थित एच. एम. टी. कारखाने की उत्पादन क्षमता का विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने के लिए कोई योजना बनायी गई है, और

(ड) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सूखबीर सिंह बादल)ः (क) एच.एम. टी. की 22 यूनिटों के राज्य वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैः-

आंध्र प्रदेश	4	असम	1
हरियाणा	2	जे. एंड के	1
केरल	2	कर्नाटक	8
महाराष्ट्र	1	पंजाब	8
राज्सथान	1	यू.पी.	1

(ख) औऱ (ग) तीन वर्षों के दौरान, एच.एम.टी. की अजमेर यूनिट का उत्पादन लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धि निम्न प्रकार हैः

(रुपये लाख मे)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति प्रतिशत
1995-96	2285	2857	125
1996-97	2800	3775	135
1997-98	3800	3736	98

कमी का कारण, ग्राहक द्वारा माल उठाने में हुआ, विलम्ब रहा है।

(ङ) औऱ (ड) एच.एम.टी. कंपनी के लिए एक पुनरुद्धार योजना पर काम कर रही है। विस्तार तथा आधुनिकीकरण को पुनरुद्धार योजना के एक भाग रुप में समझा जा सकता है।

Steps to remove bottlenecks in Industrial policies

3560. MISS SAROJ KHAPARDB: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that liberalisation is not delivering the desired results in the industrial sector in the country;

(b) whether Government have identified the bottlenecks in the industrial policies of the Central and State Governments;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the action Gvoemment propose to take to remove these bottlenecks so that more and more industries are set up in the country?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRIiSIKANDER BAKHT) (a) to (d) The pcocess of economic liberalisation started, in the year 1991-92, resulted in the increased industrial production during - 1993-94, 1994-95 and 1995-96. when the growth rate improved by 6.0%, 8.4% and 12.7% respectively. However, inspite of strong fundamentals of the economy there was a slow down in the growth of the industrial production during 1996-97 and 1997-98, when the industrial sector grew by 5.6% and 6.6% respectively. This slow down in the industrial production was due to a combination of factors which include slump in the capital market, dampening investment activity, infrastructural constraints and sluggish export growth which was due to decline in the growth of world trade.

The review of the Industrial policy is an on-going process. The recent steps taken for liberalising the Ind«ittiilbl Policy

and streamlining the procedures include further delicensing of industries; 35% increase in plan outlay on the infrastructure; permitting Foreign Direct Investment (FDI) up to Rs. 1500 crore for power projects through the automatic approval route and time bound clearance for FDI proposals in general.

उद्योगों में महिला उद्यामी

3561. **श्री गोविन्दराम मिरीः** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस समय विभिन्न उद्योगों मे महिला उद्यमियों का कुल प्रतिशत कितना है,

(ख) क्या सरकार ने औद्योगिक एकक स्थापति करने हेतु महिला उद्यमियों के लिए कोई प्रोत्सहान योजना तैयार की है,

(ग) ऐसे कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें महिला उद्यमियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, और

(घ) प्रति वर्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में से महिला आवेदकों की सख्या का अनुपात/संख्या का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त):(क) द्वितीय अखिल भारतीय पंजीकृत लघु औद्योगिक एकक संगणना (उपलब्ध सद्यतन स्थिति) के अनुसार 31.03.1988 को लघु क्षेत्र में महिला उद्यमियों की प्रतिःशतता 7.69ज्% थी। बड़े और मझौले क्षेत्र की महिला उद्यमियों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां । नये औद्योगिक एककों को स्थापित करने के लिए महिला उद्यमियों को प्रदान किये जा रहे अनेक प्रकार के प्रोत्साहन निम्नलिखित हैः-

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिड़बी) द्वारा महिला उद्यमियों के लिए पुनः पुनर्वित पोषण योजना

सिड़बी द्वारा महिला उद्यम निधि योजना के अंतर्गत सुलभ ऋण (सॉफ्ट लोन) के माध्यम से इक्रिटी जैसी सहायता।

सिड़बी ने महिलाओं के लिए कुछ विकासात्मक कार्यकश बनाने हैं जैसे कि महिला विकास निधि, लघु (माइकों) ऋण योजना, महिला उद्यमित्ता विकास कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम और विपणन विकास निधियां।

लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस. आई. एस. आई.) राज्य उद्योग निदेशालय और बैंक महिलाओं के लिए उद्यमियता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन अनन्य रुप से कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.) के अंतर्गत महिलाओं को औद्योगिक एककों व्यवसाय औऱ सेवा उद्यमों की स्थापना करने के लिए तरजीह दी जाती है।

सरककर ने महिलाओं में उद्यमियता का अनन्य रुप से विकास और संवर्धन करने के लिए व्यापार संबद्व उद्यमियता सहायता औऱ विकास (ट्रेड) नामक शीर्षक कार्यक्रम स्वीकृत प्रदान कर दी है।

(घ) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों का अधिकतम संकेन्द्रण आन्ध्र प्रदेश. महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया गया था।

(ङ) प्रधान मंत्री रोजागार योजना जिसके अंतर्गत उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र है, के अंतर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 की अपेक्षित सूचना निम्र प्रकास हैः-

वर्ष	प्राप्त आवेदनों कीकुल संख्या	महिलाओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या / अनुपात
1995-96	9,60,162	90,333(9.4%)
1996-97	8,90,746	90,847(10.2%)
1997-98	7,69,972	90,036(12.1%)

Integrated InficBstructural Developm*:.

3562. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the scheme of Integirakd Infrastructural Development (IID) (including Technical back up Services) for Small Scale Industries in rural and backward areas is not becoming successful;

(b) if so, the reasons therefor and the remedial steps being taken to make it a raccess;